भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3968

मंगलवार, 17 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

औद्योगिक विकास के लिए बजट 2026-27 में निधि का आवंटन

3968. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः
डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरीः
श्रीमती भारती पारधीः
श्री नरेश गणपत म्हस्केः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बजट 2026-27 के अंतर्गत रणनीतिक आवंटन औद्योगिक विकास को गति देने और 'विकसित भारत' की परिकल्पना को आगे बढ़ाने की स्पष्ट प्रतिबद्धता के अनुरूप है;

(ख) क्या घरेलू विनिर्माण और मूल्य श्रृंखला एकीकरण पर जोर देने से भारत की वैश्विक उत्पादन केंद्र के रूप में स्थिति सुदृढ़ होती है;

(ग) क्या बजट के अंतर्गत राजकोषीय प्रोत्साहन और लक्षित क्षेत्रक सहायता पूंजी निवेश, प्रौद्योगिकी अपनाने और औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए किए गए हैं;

(घ) क्या नियामक युक्तिकरण और अनुपालन में कमी संबंधी उपायों के फलस्वरूप सभी सेक्टरों क्षेत्रों के उद्योगों के लिए व्यापार करने में सुगमता की स्थिति में सुधार हुआ है;

(ङ) क्या औद्योगिक रोडमैप के अंतर्गत अवसंरचना विस्तार और संभार तंत्र संबंधी सुधार प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाते हैं और उत्पादन लागत को कम करते हैं; और

(च) क्या बजट 2026-27 में समन्वित राजकोषीय और ढांचागत सुधार दीर्घकालिक औद्योगिक आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए एक स्थायी आधार प्रदान करते हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (च): केंद्रीय बजट 2026-27 औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने और विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, अवसंरचना तथा औद्योगिक ईकोसिस्टम में निवेश के माध्यम से 'विकसित भारत' की परिकल्पना को आगे बढ़ाने की स्पष्ट रणनीतिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस बजट में घरेलू विनिर्माण को सुदृढ़ करने, मूल्य-श्रृंखला के एकीकरण को मजबूत बनाने और उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है, जिससे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी उत्पादन केंद्र के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होगी।

इस बजट में सेमीकंडक्टर, बायोफार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, पूंजीगत वस्तुएं और वस्त्र जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में पूंजी निवेश, प्रौद्योगिकी को अपनाने और औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए लक्षित राजकोषीय प्रोत्साहन तथा क्षेत्रगत सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, सरकार ने विनियामक यौक्तीकरण, अनुपालन में कमी और कर एवं श्रम फ्रेमवर्क सरल बनाने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखा है, ताकि सभी क्षेत्रों के उद्योगों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार हो सके।

इन उपायों के पूरक के रूप में, इस बजट ने अवसंरचना विस्तार और लॉजिस्टिक्स दक्षता पर बल प्रदान करने के क्रम को बरकरार रखा है, जिसमें औद्योगिक कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और घरेलू विनिर्माण की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 12.2 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय प्रस्तावित है।

कुल मिलाकर, विनिर्माण प्रोत्साहन, क्लस्टर विकास, एमएसएमई को सहायता, अवसंरचना निवेश और प्रौद्योगिकी-आधारित औद्योगीकरण को शामिल करते हुए ये समन्वित राजकोषीय और संरचनात्मक सुधार, विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप, दीर्घकालिक औद्योगिक आत्म-निर्भरता, उत्पादकता वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए एक स्थायी आधार प्रदान करते हैं।

बजट 2026-27 में घोषित प्रमुख औद्योगिक पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ाना

i. बायोफार्मा 'शक्ति' के तहत पांच वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के लिए घरेलू

ईकोसिस्टम का निर्माण करना ताकि विश्व स्तर पर बायोफार्मास्यूटिकल्स विनिर्माण में भारत की स्थिति मजबूत हो सके।

ii. भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) 2.0 का उद्देश्य घरेलू सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जिसमें उपकरण, सामग्रियों और पूर्ण-स्टैक भारतीय आईपी विकास के साथ-साथ आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करना शामिल है।

iii. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण ईकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण स्कीम का विस्तार, जिसके लिए 22,919 करोड़ रुपए के परिव्यय को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

iv. खनिज-संपन्न राज्यों में दुर्लभ मृदा कॉरिडोरों का विकास करना, ताकि महत्वपूर्ण खनिजों के खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके।

v. घरेलू रासायनिक विनिर्माण को सुदृढ़ करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए क्लस्टर-आधारित प्लग-एंड-प्ले मॉडल के माध्यम से तीन रासायनिक पार्कों की स्थापना करना।

2. पूंजीगत वस्तुओं और औद्योगिक विनिर्माण क्षमता को सुदृढ़ करना

i. हाई-प्रीसिशन वाले घटकों के डिजाइन और विनिर्माण के लिए सीपीएसई द्वारा स्वचालित सेवा ब्यूरो के रूप में हाई-टेक टूल रूम की स्थापना।

ii. प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत उपकरणों के घरेलू उत्पादन को सुदृढ़ करने के लिए निर्माण और अवसंरचना उपकरण (सीआईई) विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए स्कीम।

iii. वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंटेनर विनिर्माण ईकोसिस्टम तैयार करने के लिए पांच वर्ष हेतु 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली कंटेनर विनिर्माण स्कीम।

3. श्रम-प्रधान विनिर्माण का विस्तार करना

i. एकीकृत वस्त्र क्षेत्र कार्यक्रम, जिसमें राष्ट्रीय रेशा स्कीम, वस्त्र विस्तार और रोजगार स्कीम, टेक्स-ईको पहल और समर्थ 2.0 के साथ-साथ

मेगा टेक्सटाइल पार्क शामिल हैं, ताकि मूल्य संवर्धन, रोजगार सृजन और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा दिया जा सके।

ii. महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल ताकि बाजार लिंकेज, ब्रांडिंग, कौशल विकास और गुणवत्ता सुधार के जरिए खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों को मजबूती प्रदान की जा सके।

iii. खेल-कूद की सामग्रियों के विनिर्माण के लिए समर्पित पहल, ताकि उपकरण डिजाइन और सामग्री विज्ञान में नवप्रयोग को प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके।

4. औद्योगिक क्लस्टर का पुनरुद्धार करना

i. अवसंरचना आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से 200 विरासती औद्योगिक क्लस्टरों के पुनरुद्धार हेतु स्कीम, जिसका उद्देश्य लागत संबंधी प्रतिस्पर्धात्मकता, उत्पादकता और एमएसएमई की मूल्य श्रृंखलाओं के एकीकरण में सुधार करना है।

इस प्रकार, केंद्रीय बजट 2026-27 में एक व्यापक औद्योगिक विकास रणनीति प्रस्तुत की गई है, जिसमें क्षेत्र-विशिष्ट राजकोषीय सहायता, उन्नत विनिर्माण पहलें, क्लस्टर विकास और अवसंरचना विस्तार को शामिल किया गया है। इन उपायों को, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ भारत के एकीकरण को सुदृढ़ करते हुए, पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। समग्र रूप से ये सभी उपाय औद्योगिक आत्म-निर्भरता, उत्पादकता वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए एक मजबूत और स्थायी फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं, जो भारत को विकसित भारत बनने के पथ पर अग्रसर करने में सहायक है।

*****